



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 894 राँची, सोमवार, 11 नवम्बर, 2019 (ई०)

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

##### अधिसूचना

25 अक्टूबर, 2019

अधिसूचना संख्या-8/अधि०/104/2012/न०वि०आ०-5342-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 (यथा संशोधित) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा “झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 (यथा संशोधित)” में निम्नवत् संशोधन करते हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

- (1) यह नियमावली “झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली, 2019” कही जायेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. “झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 (यथा संशोधित)” के अध्याय-3 के नियम-6 के उपनियम (1)(क)(i) में परन्तुक निम्नवत् समाविष्ट किया जाता है-

“परंतु यह कि नियम 6(1) के अधीन सर्वप्रथम अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो चुके हों, के आधार पर यथास्थिति तीनों श्रेणी (नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत) के नगरपालिकाओं की कुल जनसंख्या के अनुसार महापौर/अध्यक्ष के पदों में अनुसूचित

जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य के लिए, राज्य की कुल जनसंख्या के अनुसार अधिनियम की धारा 27(2) के अधीन इन कोटियों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कर कुल कोटिवार पदों की संख्या निर्धारित की जाएगी। तत्पश्चात् उन नगरपालिकाओं, जिनका निर्वाचन पूर्व में सम्पन्न हो चुका है और उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, के कोटिवार आरक्षित पदों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य) की संख्या को कुल निर्धारित कोटिवार आरक्षित पदों की संख्या में से घटाकर अवशेष नगरपालिका, जिनका निर्वाचन कराया जाना है, में आरक्षण एवं आवंटन की कार्यवाई की जाएगी।”

3. “झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 (यथा संशोधित)” के उपाबद्ध अनुसूची के उदाहरण (1) (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के गठन एवं आरक्षण के अवधारण की प्रक्रिया) की कंडिका-8(ख) के पश्चात् कंडिका-8(ग) निम्नवत् समाविष्ट जाता है-

“यदि अन्य विकल्प नहीं हो, तब पूर्ववर्ती निर्वाचन में किसी कोटि विशेष/महिला के लिए आवंटित निर्वाचन क्षेत्र उसी कोटि/महिला के लिए पश्चात्पूर्वी निर्वाचन में पुनः आवंटित किया जा सकेगा।”

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अजय कुमार सिंह,**  
सरकार के सचिव।

-----